POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2013/अंक 12 कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, आरएमएस (पी.एस.ओ.) जयपुर-06

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2013 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! राजस्थान विधानसभा के चुनाव इस माह की एक तारीख को कुल मिलाकर शांतिपूर्वक सम्पन्न हो गए। इस बार मतदाता के पास वोटिंग मशीन में 'नोटा' वाला बटन अर्थात नापसन्दगी का विकल्प भी मौजूद था। इससे मतदाताओं ने काफी सोच- समझ कर अपने मत का उपयोग किया है।

जनता संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन चाहती है। प्रजातंत्र में एक संवेदनशील व हितकारी सरकार वह है जो जनता के द्वारा, जनता के लिए हो। देश में जनता के द्वारा तो सरकार चुनी जाती है, लेकिन चुनी गई सरकार वास्तविक अर्थों में जनता के लिए हो, यह अभी भी एक स्वप्न बना हुआ है। इस स्वप्न को साकार करने व सुशासित सरकार बनाने का भार अब चुने गए विधायकों पर है।

सुशासन के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शिता एवं जवाबदेहिता का होना अति आवश्यक है। चुने गए विधायकों को अपना स्वयं का हित व स्वार्थ त्याग कर जनता के प्रति समर्पित होना चाहिए। उन्हें संकल्प लेना होगा कि वे जनसेवा की आड़ में किसी भी तरह से भ्रष्टाचार व अनैतिक कामों में लिप्त नहीं रहेंगे।

यह अच्छी बात है कि लोग अब राजनीतिक सुधारों की अहमियत को समझने लगे हैं। उनकी पैरवी के लिए सामाजिक संस्थाएं भी आगे आ रही हैं। जरूरी यह भी है कि देश के नागरिक स्वयं अपने कर्तव्यों के प्रति सुअनुशासित रह कर देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। देश तभी सुशासित हो सकेगा, जब जनता खुद जागरूक होगी।

घोषणा-पत्र पर हो अमल

चुनाव के ऐन मौके पर राजनीतिक दल अपने घोषणा-पत्र जारी करते हैं। इनमें जनता से उनकी भलाई और प्रदेश के विकास के बढ़-चढ़ कर वादे किए जाते हैं। सत्ता मिलने के बाद सत्ताधारी दल को घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए समयबद्ध रूपरेखा तैयार करनी चाहिए।

घोषणाओं की प्राथमिकताएं तय करने के लिए जनता से भी सुझाव आमंत्रित किए जा सकते हैं। सुशासन की दृष्टि से क्षेत्रवार स्थानीय लोगों से भी उनकी जरूरतों और समस्याओं के बारे में जानकारी लेना और उनका समयबद्ध रूप से समाधान करना आवश्यक है। इससे जनता के हितों और देश व प्रदेश के विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता साबित हो सकेगी।

अमूमन रूप से देखा गया है कि सरकार शुरू में दिखावे के नाम पर घोषणा पत्र में वर्णित कुछ घोषणाओं पर अमल शुरू करती है। कुछ समय बाद ही संबंधित विभागों में घोषणा पत्र की फाइलों पर धूल जमना शुरू हो जाती है। जनता को ऐसे विभागों के मंत्रियों से जवाब मांगने का अधिकार मिलना चाहिए।

भ्रष्टाचार मुक्त हो प्रशासन

देश में भ्रष्टाचार एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। पिछले दिनों ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की ओर से भ्रष्टाचार पर किए गए एक विश्वव्यापी सर्वेक्षण में भारत के राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा भ्रष्ट संस्थानों में बताया गया है। एक अन्य सर्वे के अनुसार 2004 से अब तक जितने विधायक और सांसद दोबारा चुनाव जीते हैं, उनकी सम्पत्ति में बहुत ज्यादा बढ़ोत्तरी दर्ज हुई है। राजनीति में बड़ी तेजी से अपराधियों का बोलबाला बढ़ने से भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ रहा है। लोगों की नजर में बेशुमार दौलत कमाने के लिए राजनीति एक व्यवसाय बनता जा रहा है।

लोगों का कहना है कि जब मंत्री स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, तो प्रशासनिक व्यवस्था में ऊपर से लेकर नीचे तक तेजी से भ्रष्टाचार पनपता है। इससे विकास अवरुद्ध हो जाता है, जिसका सबसे ज्यादा बुरा असर गरीबों पर पड़ता है। मसलन, मनरेगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का हश्र हमारे सामने है। कई अन्य योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार तो उजागर ही नहीं हो पाते। भ्रष्टाचार के कई मामलों में राजनेताओं के शामिल होने के कारण योजनाओं में हुए घपलों की जांच दबा दी जाती है। इससे सम्बन्धित राजनीतिक पार्टी की छवि धूमिल होती है, वहीं भ्रष्टाचारियों का हौसला और बढ़ जाता है।

मिटाएं जातिवाद का फण्डा

जाति और मजहब के नाम पर वोट बैंक बनाने की राजनीति ने देश को खोखला कर दिया है। राजनीतिक दल चुनाव में अपना बहुमत जुटाने और सरकार बनाने के लिए जिताऊ उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं। मद्देनजर क्षेत्रवार जाति, धर्म, और राजनीतिक परिवारों में से उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं। वे जाति व धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाते हैं।

तिकड़मबाजी से योग्यता व अच्छी छवि नहीं होने के बावजूद वह जीत जाते हैं। जीतने के बाद वे केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगते हैं। इससे आम लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पाता। जातिवाद और मजहब की दीवार हमारे सामाजिक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर रही है। जबकि लोकतंत्र में अच्छी सरकार के लिए ईमानदार, स्वच्छ छवि वाले सुयोग्य जनप्रतिनिधि को प्रमुखता दी जानी चाहिए।

योग्यता पर हो खास ध्यान

राजस्थान की तेरहवीं विधानसभा में 22 विधायक ऐसे चुन कर आए थे जो केवल आठवीं कक्षा तक पढ़े थे और 13 विधायक केवल मैट्रिक पास थे। जबकि सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में मामूली पदों के लिए शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित है। अहम प्रश्न यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को इससे अलग रहने की छूट क्यों?

योग्यता के अभाव में विधान सभा में वे मूक दर्शक बने रहते हैं। न तो वे अपने क्षेत्र की समस्याओं को रख पाते हैं, न ही किसी प्रकार की बहस में हिस्सा लेते हैं। ऐसे में मंत्री बनने पर नौकरशाही उन पर हावी हो जाती है। मंत्री की कमियों का फायदा नौकरशाही उठाती है।

सुधारों एवं सुझावों को दें अहमियत

जनहित में न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, स्वयंसेवी सामाजिक संस्थाएं, मीडिया आदि समय-समय पर देश-प्रदेश की राजनीतिक स्वच्छता और सुशासन के मद्देनजर सरकार को निर्देश और सुझाव देते हैं। सरकार व राजनीतिक दलों को इन्हें अहमियत प्रदान करते हुए दलगत नीतियों से ऊपर उठ कर नि:स्वार्थ रूप से विचार कर निर्णय लेना चाहिए।

स्वार्थपूर्ण लिए गए निर्णय से सरकार की खिल्ली ही नहीं बल्कि आमजन में अविश्वास की धारणा बनती है। जनलोकपाल बिल, राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने, सीबीआई को स्वतंत्रता देने और दागियों को चुनाव न लड़ाने के मामले ज्वलंत उदाहरण हैं।

योजनाओं का हो प्रभावी क्रियान्वयन

सरकार जनता की भलाई और विकास को दृष्टिगत रख कर अनेक योजनाएं बनाती है। इनमें कई योजनाएं आम लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित होती है। इन योजनाओं के लिए बजट में काफी धन राशि खर्च करने के प्रावधान भी किए जाते हैं।

अमूमन प्रशासनिक कमजोरियों व सही निगरानी व्यवस्थाएं नहीं होने के कारण इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन नहीं हो पाता। कई योजनाओं में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है। इससे वास्तविक हकदारों तक योजनाओं के पूरे लाभ नहीं पहुंच पाते। इसके लिए प्रशासनिक व्यवस्थाओं में सुधार के साथ-साथ योजनाओं में जनभागीदारी एवं सामुदायिक निगरानी बढ़ाकर भी क्रियान्वयन में सुधार किए जा सकते हैं।

जनप्रतिनिधियों में हो जवाबदेही

सुशासन के लिए नियंत्रण जरूरी है! जबसे 'सूचना का अधिकार' आम आदमी के हाथों में आया है, तब से कई समस्याओं का समाधान आसान हो गया है। इस कानून से सरकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के छोटे-बड़े अनगिनत मामले आम जनता के सामने उजागर हुए हैं। इससे सरकारी मशीनरी और उसके काम करने के ढंग में परिवर्तन की झलक दिखाई देने लगी है।

इस कानून में शासक वर्ग की मानसिकता बदलने तक की क्षमता है। मद्देनजर केन्द्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों को इस कानून के दायरे में लाने का एक उचित निर्णय दिया था। लेकिन शासक वर्ग ने इसके खिलाफ संशोधन लाकर इसे उलट दिया। इससे जनता में शासक वर्ग के प्रति अविश्वास की भावना जागृत हुई है। राजनीतिक दल जब दूसरों से पारदर्शी होने की अपेक्षा करते हैं, तो वे खुद क्यों पारदर्शी व जवाबदेह नहीं होना चाहते?

दागियों को नहीं दें मंत्री पद

सुशासन के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता चुनाव में दागियों को उम्मीदवार नहीं बनाएं। चुनाव से पूर्व वे इसके लिए जनता को भरोसा भी देते रहते हैं कि अपराधिक छवि के लोगों को चुनाव में उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। लेकिन जिताऊ उम्मीदवार के नजरिए से अपराधिक छवि के लोगों अथवा उनके परिवारजनों को टिकट दे दिए जाते हैं।

इनके कारण चुनाव में अपराधिक और हिंसक घटनाएं होती हैं। क्षेत्र के लोगों को आतंकित कर वे चुनाव में जीत भी जाते हैं। राजनीतिक दल के प्रमुख इनकी गतिविधियों से वाकिफ होने के बावजूद दबाव में आकर उन्हें मंत्री भी बना देते हैं। इससे न केवल पार्टी की छवि पर बुरा असर पड़ता है, बल्कि यह आगे जाकर व्यवस्था को भ्रष्ट बना देते हैं।

प्रकाशित हो विधायक का लेखा-जोखा

साल में एक बार सभी विधायकों के कामकाज का लेखा-जोखा प्रकाशित होना चाहिए, ताकि जनप्रतिनिधि सतर्क रहें और जनता की आवाज को विधान सभा में उठाएं।

विधायकों को जन हित के मुद्दों पर आगे रह कर विधान सभा में आवाज उठानी चाहिए। जिन लोगों ने वोट दिए हैं उन्हें मालुम होना चाहिए कि आखिर उनका विधायक क्या करता है।

अफसर न माने जुबानी आदेश-कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने नौकरशाहों को राजनीतिक दबाव से बड़ी राहत प्रदान की है। कोर्ट ने उन्हें यह अधिकार दिया है कि वे राजनीतिक आकाओं के जुबानी आदेश को फाइल पर दर्ज करें, ताकि किसी निर्णय के लिए उन्हें बाद में परेशान नहीं किया जा सके। न्यायाधीश के.एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जुबानी की जगह लिखित आदेश से पारदर्शिता को बढ़ावा मिलेगा।

सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला नौकरशाही के कामकाज को सुधारने में मील का पत्थर साबित होगा। नौकरशाहों की किसी एक पद पर न्यूनतम अवधि तय करने तथा मौखिक आदेशों पर काम नहीं करने की छूट देना, निश्चित रूप से उनमें एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा।

सुशासन केवल नारा नहीं

प्रदेश में चल रही सार्वजनिक वितरण प्रणाली निगरानी के अभाव और भ्रष्टाचार के कारण विफल है। इसी विभाग और राशन डीलरों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा योजना कैसे सुचारू रूप से लागू हो सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो नागरिक अधिकार-पत्र बना हुआ है, उसमें अंकित सतर्कता समितियां है ही नहीं।

इसी तरह कई सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार के जाल में फंसी हैं। जवाब-देहिता, पारदर्शिता, सुशासन केवल नारा नहीं है। इसके लिए सार्थक प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे नारे की वास्तविक क्रियान्विति हो सके।

-हरि प्रसाद योगी, सवाई माधोपुर

नई सरकार से अपेक्षा

प्रदेश की नई सरकार से हम चाहते हैं कि प्रदेश में शिक्षित युवाओं में जो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है उसे दूर किया जाए। उन्हें रोजगार से जोड़ने में प्राथमिकता दी जाए। मनरेगा जैसी योजनाओं की प्रभावी क्रियान्विति हो। इसके लिए निगरानी व्यवस्था को भी मजबूत किया जाए।

भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का अभियान चले और उन्हें सख्त सजा दी जाए। टैक्स में कमी कर कमरतोड़ महगांई से लोगों को राहत दी जाए। प्रदेश में निर्धन व कमजोर वर्ग को भूख से निजात व कुपोषण को समाप्त करने के लिए खाद्य सुरक्षा योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित किया जाए।

-गेहरी लाल जोशी, उदयपुर

जरूरी है सार्थक बहस

तेरहवीं विधानसभा में अब तक की सबसे कम बैठकें हुई हैं। इस अवधि में 64 दिन हंगामों के कारण बेकार चले गए। कोई सार्थक बहस नहीं हुई। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि विधानसभा में शोरगुल, पक्ष-विपक्ष की आपसी तना-तनी, छोटे-छोटे मुद्दों पर बहिर्गमन व कार्यवाही नहीं चलने देना जैसी हरकतें अब आम जनता को नहीं सुहाती।

जनता चाहती है कि सरकार और विपक्ष देशहित और जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस को अहमियत दें। इससे हमारे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती मिलेगी और धरातल स्तर तक स्थाई विकास को बल मिल सकेगा।

-राजेन्द्र पल्लीवाल, बीकानेर

युवा निभाएगें बड़ी भूमिका

अगले साल अप्रेल में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। देश में करीब 14 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे युवा है जो 2014 के इस चुनाव में पहली बार वोट दे रहे होंगे।

आज जाति और धर्म के आधार पर वोट बैंक की राजनीति ने देश को खोखला कर दिया है। भ्रष्टाचार चरम पर है। राजनीतिक चन्दा भी इस भ्रष्टाचार की जड़ है। राजनेता तो अपने आपको किसी भी कानून से ऊपर मानते हैं। न्यायपालिका के फैसलों व निर्देशों की पालना नहीं करना अपना अधिकार समझते हैं। अब लोकसभा चुनावों में युवा शक्ति एक बड़ी भूमिका निभाएगी।

- कुलदीप नागर, बांसवाड़ा

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोन: 228 2821 से 23 फैक्स: 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कटूस' जयपुर